



उचित और लाभकारी मूल्य (FRP)

प्रलिस के लिये:

उचित और लाभकारी मूल्य (FRP), गन्ना ।

मेन्स के लिये:

कृषि मूल्य निर्धारण, भारतीय अर्थव्यवस्था में चीनी उत्पादन, गन्ना उद्योग के समक्ष चुनौतियाँ ।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक सरकारी प्रस्ताव जारी किया गया जो चीनी मलों को दो चरणों में मूलभूत उचित और लाभकारी मूल्य (Fair and Remunerative Price- FRP) का भुगतान करने की अनुमति प्रदान करेगा ।

प्रमुख बिंदु

सरकार द्वारा जारी प्रस्ताव में बदलाव:

- पहली कश्त का भुगतान गन्ने की डलिवरी के 14 दिनों के भीतर करना होगा और यह ज़िले की औसत वसूली (Average Recovery Of The District) के अनुसार होगा ।
- अंतिम वसूली की गणना के बाद मलि बंद होने के 15 दिनों के भीतर मलि द्वारा किसानों को दूसरी कश्त का भुगतान किया जाएगा, जिसमें उत्पादित चीनी और 'बी हेवी' (B Heavy) या 'सी' शीरे ('C' Molasses) से उत्पादित इथेनॉल को ध्यान में रखकर भुगतान किया जाएगा ।
- इस प्रकार पछिले सीज़न के FRP पर निर्भर रहने के बजाय किसानों को मौजूदा सीज़न की वसूली के अनुसार भुगतान किया जाएगा ।

महाराष्ट्र में किसानों के वरिध का कारण:

- किसानों का तर्क है कि इस पद्धति से उनकी आय प्रभावित होगी तथा FRP का भुगतान कश्तों में किया जाएगा जिसमें काफी अंतर वदियमान होगा, साथ ही उसमें पूरव की तरह बैंक ऋण और अन्य खर्चों का भुगतान शामिल होने की उम्मीद है ।
- किसानों को एकमुश्त धनराशि की आवश्यकता ज़्यादातर मौसम की शुरुआत (अक्टूबर-नवंबर) में होती है क्योंकि उनका अगला फसल चक्र इसी पर निर्भर करता है ।

FRP के बारे में:

- FRP सरकार द्वारा घोषित मूल्य है जिस पर मल्लें किसानों से खरीदे गए गन्ने का भुगतान कानूनी रूप से करने के लिये बाध्य हैं ।
 - मल्लें के पास किसानों के साथ समझौते के लिये हस्ताक्षर करने का एक विकल्प है, जो मल्लें द्वारा किसानों को कश्तों में FRP का भुगतान करने की अनुमति प्रदान करता है ।
 - भुगतान में देरी पर 15% तक प्रतिवर्ष ब्याज लग सकता है और चीनी आयुक्त (Sugar Commissioner) मल्लें की संपत्तियों को संलग्न कर राजस्व वसूली के तहत बकाया के रूप में अदत्त एफआरपी (Unpaid FRP) की वसूली कर सकते हैं ।
- देश भर में FRP का भुगतान [आवश्यक वस्तु अधिनियम \(EAC\), 1955](#) के तहत जारी गन्ना नयितरण आदेश, 1966 द्वारा नयितरति होता है, जो गन्ने की डलिवरी की तारीख के 14 दिनों के भीतर भुगतान को अनविरय करता है ।
- यह कृषिलागत और मूल्य आयोग (CACP) की सफ़ारिश के आधार नरिधारति तथा आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) द्वारा घोषित किया जाता है ।
 - CACP कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है । यह एक सलाहकार निकाय है, अतः इसकी सफ़ारिशें सरकार के लिये बाध्यकारी नहीं हैं ।
 - CCEA की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है ।
- FRP [गन्ना उद्योग](#) के पुनर्गठन को लेकर [रंगराजन समिति](#) की रिपोर्ट पर आधारित है ।

FRP की घोषणा हेतु प्रमुख कारक:

- गन्ना उत्पादन की लागत ।
- वैकल्पिक फसलों से उत्पादकों की वापसी और कृषि वस्तुओं की कीमतों की सामान्य प्रवृत्ति ।
- उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर चीनी की उपलब्धता ।
- चीनी उत्पादकों द्वारा बेची गई चीनी का मूल्य ।
- गन्ने से उत्पादित चीनी की मात्रा ।
- उप-उत्पादों की बिक्री से होने वाली प्राप्त अर्थात् गुड़, खोई और उन पर आरोपित मूल्य ।
- गन्ना उत्पादकों के लिये जोखिम और मुनाफे के कारण उचित मार्जिन ।

FRP का भुगतान:

- FRP का भुगतान गन्ने से प्राप्त चीनी पर आधारित है ।
 - चीनी सीजन 2021-22 के लिये 10% की बेस रकिवरी पर FRP 2,900 रुपए प्रति टन तय किया गया है ।
- चीनी की रकिवरी (Sugar Recovery) उत्पादित चीनी तथा गन्ने की पेराई के अनुपात के बराबर होती है, जिसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है ।
- रकिवरी जितनी अधिक होगी, FRP उतना ही अधिक होगा तथा चीनी का उत्पादन अधिक होगा ।

गन्ना (Sugarcane):

- तापमान : उष्ण और आर्द्र जलवायु के साथ 21-27 डिग्री सेल्सियस के बीच ।
- वर्षा : लगभग 75-100 सेमी. ।
- मट्टि का प्रकार : गहरी समृद्ध दोमट मट्टि ।
- शीर्ष गन्ना उत्पादक राज्य : उत्तर प्रदेश > महाराष्ट्र > कर्नाटक > तमिलनाडु > बिहार ।
- ब्राज़ील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है ।
- इसे बलुई दोमट से लेकर चिकनी दोमट मट्टि तक सभी प्रकार की मृदा में उगाया जा सकता है, क्योंकि इसके लिये अच्छी जल निकासी वाली मट्टि की आवश्यकता होती है ।
- इसमें बुवाई से लेकर कटाई तक शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है ।
- यह चीनी, गुड़, खांडसारी और राब का मुख्य स्रोत है ।
- चीनी उद्योग को समर्थन देने हेतु सरकार की दो पहलें हैं- चीनी उपकरणों को वित्तीय सहायता योजना (SEFASU) और [जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति](#) गन्ना उत्पादन योजना ।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

महर्षिदयानंद सरस्वती जयंती

प्रलिस के लिये:

महर्षिदयानंद सरस्वती जयंती, आर्य समाज ।

मेन्स के लिये:

महर्षिदयानंद सरस्वती जयंती और उनका योगदान, महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व, आर्य समाज के मार्गदर्शक सिद्धांत ।

चर्चा में क्यों?

वर्ष 2022 में महर्षिदयानंद सरस्वती 26 फरवरी को मनाई जा रही है ।

- पारंपरिक हिंदू कैलेंडर के अनुसार, दयानंद सरस्वती का जन्म फाल्गुन माह में कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को हुआ था ।



//

महर्षि दयानंद सरस्वती:

■ जन्म:

- स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी, 1824 को गुजरात के टंकारा में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके माता-पिता यशोधर्मा और लालजी तिवारी रूढ़िवादी ब्राह्मण थे।
- मूल नक्षत्र के दौरान पैदा होने के कारण उन्हें पहले मूल शंकर तिवारी नाम दिया गया था।
- सत्य की खोज में वे पंद्रह वर्ष (1845-60) तक तपस्वी के रूप में भटकते रहे।
- दयानंद के विचार उनकी प्रसिद्ध कृति 'सत्यार्थ प्रकाश' में प्रकाशित हुए थे।

■ समाज के लिये योगदान:

- वह एक भारतीय दार्शनिक, सामाजिक नेता और आर्य समाज के संस्थापक थे।
 - आर्य समाज वैदिक धर्म का एक सुधार आंदोलन है और वह वर्ष 1876 में "भारत भारतीयों के लिये" के रूप में स्वराज का आह्वान करने वाले पहले व्यक्ति थे।
- वह एक स्व-प्रबोधित व्यक्ति और भारत के महान नेता थे जिन्होंने भारतीय समाज पर व्यापक प्रभाव छोड़ा।
- उनके द्वारा आर्य समाज की पहली इकाई की स्थापना औपचारिक रूप से 1875 में मुंबई (तब बॉम्बे) में की गई थी और बाद में इसका मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया था।
- उनके एक अखंड भारत के दृष्टिकोण में वर्गहीन और जातिविहीन समाज (धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर) तथा वंशिक शासन से मुक्त भारत शामिल था, जिसमें आर्य धर्म सभी का सामान्य धर्म हो।
- उन्होंने वेदों से प्रेरणा ली और उन्हें 'भारत के युग की चट्टान', 'हिंदू धर्म का अचूक और सच्चा मूल बीज' माना। उन्होंने "वेदों की ओर लौटो" का नारा दिया।
- उन्होंने चतुर्वर्ण व्यवस्था की वैदिक धारणा प्रस्तुत की जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति में पैदा नहीं हुआ हो, लेकिन उसके द्वारा पालन किये जाने वाले व्यवसाय के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र के रूप में पहचाना जाता था।

■ शिक्षा प्रणाली में योगदान:

- उन्होंने शिक्षा प्रणाली में पूरी तरह से बदलाव की शुरुआत की और उन्हें आधुनिक भारत के दूरदर्शी लोगों में से एक माना जाता है।
- स्वामी दयानंद सरस्वती के दृष्टिकोण को साकार करने के लिये वर्ष 1886 में डीएवी (दयानंद एंग्लो वैदिक) स्कूल अस्तित्व में आए।
- पहला डीएवी स्कूल लाहौर में स्थापित किया गया और महात्मा हंसराज इसके प्रधानाध्यापक थे।

आर्य समाज के बारे में:

- आर्य समाज का उद्देश्य वेदों (सबसे पुराने हिंदू धर्मग्रंथ) को सत्य के रूप में फिर से स्थापित करना है। उन्होंने वेदों में बाद की अभिवृद्धि को खारज कर दिया और अपनी व्याख्या में अन्य वैदिक विचारों को भी शामिल किया।
 - वर्ष 1920 और 1930 के दशक की शुरुआत में कई मुद्दों पर तनाव बढ़ गया। मुस्लिम "मस्जिद से पहले संगीत", गौ रक्षा आंदोलन और आर्य समाज के शुद्ध आंदोलन से नाराज़ थे।
- आर्य समाज का प्रभाव पश्चिमी और उत्तरी भारत में अधिक रहा है।
- आर्य समाज में मूर्ता पूजा का विरोध, पशु बलि, श्राद्ध (पूर्वजों की ओर से अनुष्ठान), जन्म के आधार पर जाति का निर्धारण न कियोग्यता के आधार पर, अस्पृश्यता, बाल विवाह, तीर्थयात्रा, पुजारी पद्धति और मंदिर प्रसाद की पूजा का विरोध किया जाता है।
- यह वेदों की अचूकता, कर्म सिद्धांत (पछिले कर्मों का संचित प्रभाव) और संसार (मृत्यु व पुनर्जन्म की प्रक्रिया), गाय की पवित्रता, संस्कारों के महत्त्व (व्यक्तिगत संस्कार) की प्रभावशीलता को कायम रखता है। तथा अग्नि के लिये वैदिक यज्ञों की प्रभावकारिता एवं सामाजिक सुधार के कार्यक्रमों की पुष्टि करता है।
- आर्य समाज द्वारा महिला शिक्षा के उत्थान के साथ ही अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य किया गया। विधवाओं के लिये मशिन, अनाथालय व घरों का निर्माण, स्कूलों तथा कॉलेजों का एक नेटवर्क स्थापित किया और अकाल राहत व चिकित्सा कार्य किये गए।

स्रोत: टाइम्स ऑफ इंडिया

गोबर-धन संयंत्र: SBM-U का दूसरा चरण

प्रलिस के लिये:

SBM-U का दूसरा चरण, बायोरेमेडिएशन।

मेन्स के लिये:

स्वच्छ भारत मशिन और इसका महत्त्व।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री ने इंदौर में 'गोबर-धन' (बायो-CNG) प्लांट का उद्घाटन किया है, इसका उद्देश्य लाखों टन उस अपशिष्ट को हटाना है, जो हजारों एकड़ भूमि पर कब्जा कर रहा है और वायु एवं जल प्रदूषण के कारण कई बीमारियों को जन्म दे रहा है।

- इसे स्वच्छ भारत मशिन (SBM-U 2.0) के दूसरे चरण के तहत स्थापित किया गया है।
- यह प्लांट 'जीरो लैंडफिल मॉडल' पर आधारित है। इसके अतिरिक्त इस परियोजना के कई पर्यावरणीय लाभ मिलने की भी उम्मीद है, जैसे- ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी, उर्वरक के रूप में जैविक खाद के साथ हरित ऊर्जा प्रदान करना आदि।

स्वच्छ भारत मशिन-शहरी 2.0:

परिचय:

- बजट 2021-22 में घोषित SBM-U 2.0, SBM-U का दूसरा चरण है।
- सरकार शौचालयों के माध्यम से मल और सेप्टेज के सुरक्षित निपटान की कोशिश कर रही है।
 - शहरी भारत को खुले में शौच से मुक्त (ODF) बनाने और नगरपालिका के ठोस कचरे का 100% वैज्ञानिक प्रबंधन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 2 अक्टूबर, 2014 को SBM-U का पहला चरण शुरू किया गया था। यह अक्टूबर 2019 तक चला।
- इसे 1.41 लाख करोड़ रुपए के परियोजना के साथ वर्ष 2021 से 2026 तक पाँच वर्षों में लागू किया जाएगा।
- इस मशिन को 'अपशिष्ट से धन' और 'परपितृ अर्थव्यवस्था' के व्यापक सिद्धांतों के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है।

लक्ष्य:

- यह कचरे का स्रोत पर पृथक्करण, एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक और वायु प्रदूषण में कमी, निर्माण एवं वधिवंस गतिविधियों से कचरे का प्रभावी ढंग से प्रबंधन तथा सभी डंप साइट्स के [बायोरेमेडिएशन](#) पर केंद्रित है।
- इस मशिन के तहत सभी प्रकार के अपशिष्ट जल को जल नकियों में छोड़ने से पहले ठीक से उपचारित किया जाएगा तथा सरकार द्वारा अधिकतम पुनः उपयोग को प्राथमिकता देने का प्रयास किया जा रहा है।

मशिन के परिणाम:

- सभी वैधानिक शहर ODF+ द्वारा प्रमाणित किये जाएंगे (पानी, रखरखाव और स्वच्छता के साथ शौचालयों पर केंद्रित)।
- 1 लाख से कम आबादी वाले सभी वैधानिक शहर ODF++ द्वारा प्रमाणित किये जाएंगे (कीचड़ और कीचड़ के प्रबंधन के साथ शौचालयों पर केंद्रित)।
- 1 लाख से कम आबादी वाले सभी वैधानिक शहरों का 50% से अधिक जल प्रमाणित हो जाएगा।
- कचरा मुक्त शहरों के लिये MoHUA के [कचरा मुक्त शहरों का स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल](#) के अनुसार, सभी वैधानिक शहरों को [कम-से-कम 3-स्टार कचरा मुक्त रेटिंग](#) प्रदान की जाएगी।
- सभी पुरानी डंप साइट्स का [जैवोपचारण](#) किया जाएगा।

स्रोत: पी.आई.बी.

रूस और यूक्रेन का इतिहास

प्रलिस के लिये:

रूस और यूक्रेन की भौगोलिक स्थिति, स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल (CIS) ।

मेन्स के लिये:

रूस-यूक्रेन संघर्ष, भारत के हितों पर देशों की नीतियों एवं राजनीतिका प्रभाव ।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में रूस ने यूक्रेन के दो क्षेत्रों को स्वतंत्र गणराज्यों के रूप में मान्यता दी थी, जो कअपरहार्य युद्ध का संकेत था ।

- अपनी युद्ध घोषणा के दौरान रूसी राष्ट्रपति ने यूक्रेन को बना किसी इतिहास या पहचान वाले देश के रूप में वर्णित किया है, जिसे पूरगतः पूर्ववर्ती सोवियत संघ (USSR) के हिस्से को अलग करके बनाया गया था ।
- यूक्रेन और रूस सैकड़ों वर्षों से सांस्कृतिक, भाषायी और पारिवारिक संबंध साझा करते रहे हैं ।

यूक्रेन का प्रारंभिक इतिहास:

- तकरीबन एक सहस्राब्दी पूर्व वर्तमान यूक्रेन 'कीवयाई रूस' के केंद्र में था ।
- कीवयाई रूस, पूर्वी एवं उत्तरी यूरोप के पूर्वी स्लाव, बाल्टिक और फनिकि लोगों का एक संघ था, जिसकी राजधानी कीव थी ।
 - आधुनिक यूक्रेन, रूस और बेलारूस सभी का सांस्कृतिक इतिहास 'कीवयाई रूस' में मौजूद है ।
- 10वीं और 11वीं शताब्दी में कीवयाई रूस अपने सबसे बड़े आकार पर पहुँच गया ।
- 13वीं शताब्दी के मध्य में बाइज़ेंटाइन साम्राज्य के पतन के कारण व्यापार में आई गरिबत की वजह से 'कीवयाई रूस' काफी कमज़ोर हो गया और और अंततः 'मंगोल गोलडन होर्डे' के हमले के कारण पूरी तरह से बखिर गया, जिसके बाद अंत में 1240 में 'कीवयाई रूस' को बर्खास्त कर दिया गया ।
 - बाइज़ेंटाइन साम्राज्य, जिसे बाइज़ेंटियम भी कहा जाता है, रोमन साम्राज्य का पूर्वी भाग था तथा कॉन्स्टेंटिनोपल/कुसतुंतुनिया (आधुनिक इस्तांबुल) में स्थित था, साम्राज्य के पश्चिमी आधे हिस्से के पतन के बाद भी यह उसका हिस्सा बना रहा ।
 - 'गोलडन होर्डे' स्थायी मंगोलों का एक समूह था जिन्होंने 1240 से 1502 तक रूस, यूक्रेन, कज़ाखस्तान, माल्डोवा और काकेशस पर शासन किया था ।
- 15वीं शताब्दी की शुरुआत में पूर्व 'कीवान रस' के बड़े हिस्से को लथिआनिया के बहु-नृजातीय 'ग्रैंड डची' में शामिल किया गया था ।
- वर्ष 1569 में ल्यूबेल्सकी संघ, पोलैंड, लथिआनिया के 'ग्रैंड डची' पोलिश-लथिआनियाई राष्ट्रमंडल बनाने के लिये एक साथ आए, जो उस समय यूरोप के सबसे बड़े देशों में से एक था ।
- इस घटना के लगभग एक सदी बाद आधुनिक यूक्रेनी राष्ट्रीय पहचान की शुरुआत का पता लगाया जा सकता है ।

यूक्रेन:

- **भौगोलिक स्थिति:** यूक्रेन, पूर्वी यूरोप में स्थित एक देश है । इसकी राजधानी कीव है, जो उत्तर-मध्य यूक्रेन में नीपर नदी (Dnieper River) के तट पर स्थित है । यूक्रेन की सीमा उत्तर में बेलारूस, पूर्व में रूस, आज़ोव का सागर और दक्षिण में काला सागर, दक्षिण-पश्चिम में माल्डोवा व रोमानिया तथा पश्चिम में हंगरी, स्लोवाकिया एवं पोलैंड से लगती है । सुदूर दक्षिण-पूर्व में यूक्रेन को केर्च जलडमरूमध्य (Kerch Strait) द्वारा रूस से अलग किया गया है, जो आज़ोव सागर को काला सागर से जोड़ता है ।
 - यह रूस के बाद यूरोप का सबसे बड़ा देश है, जिसका क्षेत्रफल 6,03,550 वर्ग कमी. या महाद्वीप का लगभग 6% है ।



- **जनसांख्यिकी:** जुलाई 2021 में यूक्रेन की जनसंख्या 43.7 मिलियन आंकी गई थी। इसमें से 77.8% यूक्रेनी नृजातीयता और 17.3% रूसी नृजातीयता से संबंधित थी। यूक्रेनी और रूसी भाषियों की आबादी क्रमशः 67.5% और 29.6% थी।
- **अर्थव्यवस्था:** सकल घरेलू उत्पाद और प्रतिव्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के मामले में यूक्रेन यूरोप का सबसे गरीब देश है। यहाँ लौह अयस्क और कोयले के भंडार मौजूद हैं और यह मक्का, सूरजमुखी तेल, लौह उत्पादों और गेहूँ का निर्यात करता है।
- **भारत के साथ संबंध:** एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत, यूक्रेन का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है।
 - यूक्रेन के सूरजमुखी तेल का प्रमुख निर्यातक भारत है, इसके बाद अकार्बनिक रसायन, लोहा और इस्पात, प्लास्टिक व रसायन हैं।
 - भारत से यूक्रेन को प्रमुख आयात फार्मास्युटिकल उत्पाद हैं।

यूक्रेन और रूस:

- 18वीं शताब्दी में रूस की महारानी कैथरीन द ग्रेट (1762-96) ने पूरे जातीय यूक्रेन के क्षेत्र को रूसी साम्राज्य में मिला लिया था।
- रूसीकरण की ज़ारिस्ट नीति द्वारा यूक्रेनवासी सहित जातीय पहचान और भाषाओं का दमन किया गया।
- रूसी साम्राज्य के भीतर हालाँकि कई यूक्रेनियन समृद्ध और महत्त्व के पदों पर पहुँच गए तथा बड़ी संख्या में रूस के अन्य हिस्सों में बस गए।
- प्रथम विश्व युद्ध में **3.5 मिलियन से अधिक यूक्रेनवासियों** ने रूसी साम्राज्य के पक्ष में लड़ा तथा एक छोटी संख्या ने **ऑस्ट्रो-हंगेरियन** के साथ ज़ार की सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी।
- **यूक्रेन का USSR का हिस्सा बनना:** प्रथम विश्व युद्ध के कारण **ज़ार साम्राज्य और ओटोमन साम्राज्य** दोनों का अंत हो गया।
 - मुख्य रूप से कम्युनिस्ट के नेतृत्व वाले यूक्रेनी राष्ट्रीय आंदोलन का उदय हुआ जिससे कई छोटे यूक्रेनी राज्य उभरे।
 - वर्ष 1917 की **अक्टूबर क्रांति** में बोलशेविकों के सत्ता में आने के कई महीनों बाद एक स्वतंत्र यूक्रेनी पीपुल्स रिपब्लिक की घोषणा की गई, लेकिन सत्ता के विभिन्न दावेदारों के बीच गृहयुद्ध जारी रहा, जिसमें यूक्रेनी गुट, अराजकतावादी, ज़ार साम्राज्य और पोलैंड शामिल थे।
 - वर्ष 1922 में यूक्रेन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक (USSR) संघ का हिस्सा बन गया।

USSR के पतन के बाद यूक्रेन की स्थिति:

- वर्ष **1991 में USSR को समाप्त** कर दिया गया था।
- यूक्रेन में आज़ादी की मांग कुछ वर्ष पहले से बढ़ रही थी तथा वर्ष 1990 में 300,000 से अधिक यूक्रेनवासियों ने स्वतंत्रता के समर्थन में एक मानव शृंखला बनाई।
 - इसके बाद ग्रेनाइट की क्रांति हुई जब यूक्रेन के छात्रों ने यूएसएसआर के साथ एक नए समझौते पर हस्ताक्षर न करने की मांग की।
- 24 अगस्त, 1991 में राष्ट्रपति मिखाइल गोरबाचेव को हटाने और कम्युनिस्टों को सत्ता में बहाल करने के लिये तख्तापलट की वफ़िलता के बाद यूक्रेन की संसद ने देश की स्वतंत्रता हेतु अधिनियम को अपनाया।
 - इसके बाद संसद के प्रमुख लियोनिदा क्रावचुक यूक्रेन के पहले राष्ट्रपति चुने गए।
- दिसंबर 1991 में बेलारूस, रूस और यूक्रेन के नेताओं ने औपचारिक रूप से सोवियत संघ की सदस्यता त्याग कर स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल (CIA) का गठन किया।
- हालाँकि यूक्रेन की संसद वेरखोवना राडा (Verkhovna Rada) ने कभी भी परिग्रहण (Accession) की पुष्टि नहीं की, इसलिये यूक्रेन कानूनी रूप से कभी भी CIS का सदस्य नहीं था।

रूस-यूक्रेन संघर्ष का हालिया इतिहास:

- वर्ष 2014 में रूस ने जल्दबाजी में जनमत संग्रह के बाद क्रीमिया को यूक्रेन से अलग कर दिया। यह एक ऐसा कदम था जिसने पूर्वी यूक्रेन में रूस समर्थित अलगाववादियों और सरकारी बलों के बीच लड़ाई शुरू कर दी।
- हाल ही में यूक्रेन द्वारा [उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन \(नाटो\)](#) से संगठन की सदस्यता ग्रहण करने की प्रक्रिया में तेज़ी लाने का आग्रह किया गया।
- रूस द्वारा इस तरह के कदम को "रेड लाइन" घोषित किया गया और अमेरिका के नेतृत्व वाले इस सैन्य गठबंधन का अपनी देश की सीमा के करीब विस्तार के परिणामों को लेकर चिंता व्यक्त की।
- यह रूस और यूक्रेन के बीच वर्तमान युद्ध का कारण बना है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/current-affairs-news-analysis-editorials/news-analysis/26-02-2022/print>